फार्म फॉरवर्ड

वर्ष-1, अंक-5: जनवरी 2025

जायका कृषि परियोजना-2 की मासिक ई-पत्रिका

Farm Forward

MONTHLY E-PAPER OF HPCDP (PHASE-II), JICA-ODA

कृषि विभाग के फार्मों में होगी प्राकृतिक खेती: मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू

शिमला। 10 जनवरी, 2025, हिमाचल प्रदेश में कृषि विभाग के सभी फार्मों को सिर्फ प्राकृतिक खेती पद्धति से ही खेती करने के लिए विकसित किया जाएगा। आगामी वर्ष से इन सभी फार्मों में प्राकृतिक खेती की जाएगी। ये निर्देश मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कृषि विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए दिये। उन्होंने विभाग के अधिकारियों को प्रदेश में प्राकृतिक खेती से गेहूं व मक्की उगाने वाले क्षेत्रों की मैपिंग करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कृषि विभाग के सभी फार्मों पर प्राकृतिक खेती की जाएगी ताकि किसानों को प्राकृतिक खेती करने के लिए बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती से उत्पादित गेहूं व मक्का के भंडारण के लिए हाई एंड तकनीक से भंडारण केंद्र का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश प्राकृतिक खेती के क्षेत्र में देशभर में अग्रणी राज्य बनने की ओर अग्रसर है।

उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती के दौरान यदि फसल किसी बीमारी से ग्रसित होती है तो उसका उपचार भी प्राकृतिक पद्धति से ही किया जाना चाहिए। उन्होंने प्राकृतिक खेती के बीजों का प्रमाणीकरण करने के लिए प्रक्रिया निर्धारित करने को भी कहा। सीएम ने कहा कि प्राकृतिक खेती के दृष्टिगत भूमि व बीज की जांच के लिए प्रदेश में हाई-एंड प्रयोगशालाएं खोली जाएंगी।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत करने को विशेष ध्यान दे रही है। इसी दिशा में नीतियों एवं कार्यक्रमों को लागू किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में हल्दी व अदरक के प्रसंस्करण के लिए प्रसंस्करण संयंत्र खोलने पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि चौधरी सरवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में डेयरी आधारित डिग्री पाठ्यक्रम शुरू किये जाएंगे ताकि प्रदेश के युवाओं को इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने अधिकारियों को प्राकृतिक खेती पद्धति के उत्पादों के प्रभावी विपणन के लिए ई कामर्स वेबसाइट से समन्वय करने के निर्देश भी दिए। बैठक में यह भी अवगत करवाया गया कि प्रदेश में खरीफ सीजन 2024-25 के दौरान प्राकृतिक खेती से उगाई गई 3989 क्विंटल मक्का की खरीद की गई है तथा आगामी रबी सीजन के दौरान प्राकृतिक खेती से उगाई गई 8050 क्विंटल गेहूं की खरीद का लक्ष्य रखा गया है। बैठक में कृषि मंत्री प्रो. चंद्र कुमार, उप मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया, विधायक संजय अवस्थी, मुख्यमंत्री के सचिव राकेश कंवर, सचिव कृषि सी पालरासु, निदेशक डिजिटल प्रोद्योगिक एवं नवाचार डॉ. निपुण जिंदल, निदेशक कृषि कुमुद सिंह, कृषि विपणन बोर्ड के सचिव हेमिस नेगी, मुख्यमंत्री के ओएसडी गोपाल शर्मा तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

एक वर्ष में एक लाख किसान परिवार प्राकृतिक खेती से जुड़ेंगे

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्राकृतिक खेती करने वालों का डाटा ब्लॉक स्तर पर भी एकत्र किया जाएगा, जिसे हिम परिवार डाटाबेस के साथ एकीकृत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश प्राकृतिक खेती में अग्रणी राज्य बनने की ओर अग्रसर है और राज्य सरकार अधिकतम कृषक समुदाय को लाभान्वित करने के उद्देश्य से इस लक्ष्य को प्राप्त करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है।

उप मुख्य-सचेतक केवल सिंह पठानिया ने किया जायका सिंचाई परियोजना का उद्घाटन

धर्मशाला। 28 जनवरी हिमाचल प्रदेश विधानसभा में उप मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया ने शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के तहत ग्राम पंचायत अंबाडी के गांव केटलू में जायका के तहत बनी बहाव सिंचाई परियोजना त्रैम्बला कूहल का उद्घाटन किया। किसानों को बेहतर सिंचाई सुविधा देने के लिए जायका परियोजना के तहत 1900 मीटर लंबी कूहल का निर्माण किया गया है तथा जहां भूमि कटाव हो रहा था, वहां डंगों का निर्माण किया गया है।

केवल सिंह पठानिया उप मुख्य सचेतक हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा जायका सिंचाई परियोजना का किया उद्घाटन

इस कूहल के निर्माण से क्षेत्र के लगभग 86 किसानों की 17.59 हेक्टेयर भूमि की सिंचित होगी। योजना के तहत किसानों को फसल विविधीकरण व उनकी आय की बढ़ोतरी के लिए विभिन्न कृषि तकनीकों का प्रशिक्षण भी दिया गया है तथा आगे भी दिया जाता रहेगा। इस मौका पर जिला परियोजना प्रबंधक डॉ. योगेन्द्र पाल कौशल ने उप मुख्य सचेतक हिमाचल प्रदेश सरकार केवल सिंह पठानिया का स्वागत करते हुए बताया कि जायका द्वारा शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के तहत सात परियोजनाएं चलाई जा रही है, जो जल्द किसानों को समर्पित की जाएगी। इसके तहत करीब 350 हेक्टर भूमि को सिंचाई सुविधा मिलेगी।

इस मौके पर एसडीएम शाहपुर करतार चंद, अधिशाषी अभियंता जल शक्ति विभाग कैप्टन अमित डोगरा, एसडीओ लोक निर्माण विभाग बलबीत दियोलिया, ऋषि सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे।

अब तक सबसे अव्वल: जिला परियोजना प्रबंधन इकाई मंडी में 19 सिंचाई परियोजना का कार्य पूरा

मण्डी/सोलन। जिला परियोजना प्रबंधन इकाई, मंडी के अंतर्गत आने वाली चारों इकाइयां और जिला परियोजना प्रबंधन इकाई, सोलन की तीनों इकाइयां पूरे जोरों से अपने यहां चल रही सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करके स्थानीय किसान विकास संघों को सौंप रही है। अब तक जिला परियोजना प्रबंधन इकाई, मंडी द्वारा 19 सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण कार्य पूरा करने के 10 सिंचाई परियोजनाओं को स्थानीय किसान विकास संघों को सौंप दिया है और जल्द ही बाकियों को सौंपने की तैयारी में है। इन 19 सिंचाई परियोजनाओं का कुल कमांद क्षेत्र लगभग 330.2 हेक्टर है, इनके बनने से लगभग 1703 किसान परिवार लाभान्वित हो रहें हैं। इसी तरह जिला परियोजना प्रबंधन इकाई, सोलन ने अब तक 18 सिंचाई परियोजनाओं को पूरा कर लिया है जिसमें से 10 सिंचाई परियोजनाओं को किसान विकास संघों को सौंप दिया है। इन 18 सिंचाई परियोजनाओं का कुल कमांद क्षेत्र लगभग 386.88 हेक्टर और लगभग 1186 किसान परिवार लाभान्वित हो रहें हैं। इसके साथ ये चारों जिला परियोजना प्रबंधन इकाइयों में अब तक सबसे अव्वल है इसके बाद जिला परियोजना प्रबंधन इकाई, पालमपुर ने अब तक 11 सिंचाई परियोजनाओं को पूरा किया है जिसमें से 3 को किसान विकास संघों को सौंप दिया है वहीं जिला परियोजना प्रबंधन इकाई, हमीरपुर ने अब तक 1 सिंचाई परियोजना को पूरा किया है।

बीपीएमयू सरकाघाट के अंतर्गत बहाव सिंचाई योजना बजगेर खड्ड से भरयाड़ा धातड़ी कैवीए को सौंपी।

बीपीएमयू सोलन के अंतर्गत बहाव सिंचाई योजना दत्यार कैवीए को समर्पित।

जायका की विशेषज्ञ टीम ने जायका कृषि परियोजना चरण-1 के क्षेत्रों का किया दौरा

हमीरपुर, मण्डी और पालमपुर। जापान अंतरराष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (जायका) द्वारा वित्त पोषित हिमाचल प्रदेश फसल विविधीकरण प्रोत्साहन परियोजना चरण 1 कृषि विभाग द्वारा 2011 से 2020 तक हिमाचल प्रदेश के पांच जिलों कांगड़ा, मंडी, हमीरपुर, बिलासपुर और ऊना में लागू की गई थी। इस समय किये गये विभिन्न कार्यों के परिणामों का मूल्यांकन करने के लिए आजकल जायका की विशेषज्ञ टीम कांगड़ा, मंडी, हमीरपुर के किसानों से मिलकर मूल्यांकन कर रही है जिसका मुख्य उद्देश्य सिंचाई सुविधाओं के निर्माण और परियोजना के कार्यान्वयन से किसानों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति पर पड़े प्रभाव का आंकलन करना है। इस विशेषज्ञ टीम के मुख्य सदस्य श्री तोमू मोचिदा (जेआईसीए बाह्य मूल्यांककर्ता ओपीएमएसी), सुश्री काओरी ओसोन (मूल्यांकन विशेषज्ञ ओपीएमएसी) और श्री नवनीत यादव (राष्ट्रीय सहायक स्वतंत्र सलाहकार) हैं। विशेषज्ञ टीम के द्वारा हिमाचल प्रदेश फसल विविधीकरण प्रोत्साहन परियोजना (चरण-2) के मुख्यालय का दौरा किया, जायका विशेषज्ञ टीम का स्वागत परियोजना निदेशक डॉ. सुनील चौहान के द्वारा किया गया। परियोजना के मुख्यालय, हमीरपुर में बैठक का आयोजन किया गया जिसकी अध्यक्षता परियोजना निदेशक के द्वारा की गई जिसमें विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई इसके साथ ही दौरे सबंधित सभी परियोजनाओं के अधिकारियों को निर्देश दिये गये। जाइका की विशेषज्ञ टीम के द्वारा द्वारा हमीरपुर उठाऊ सिंचाई परियोजना बलेटा का दौरा किया तथा उपस्थित लाभार्थियों से विस्तृत चर्चा करते हुए उनसे जाना कि इस सिंचाई परियोजना के बनने से उनके जीवन में आर्थिकी को मध्यनजर रखते हुए क्या बदलाव आये। विशेषज्ञ टीम के द्वारा खंड परियोजना प्रबंधन, पालमपुर के अंतर्गत मुनेहड़ और सपदूहल कूहल सिंचाई योजनाओं, खंड परियोजना प्रबंधन, देहरा के अंतर्गत दडू कूहल और गेला कूहल तथा खंड परियोजना प्रबंधन, धर्मशाला के अंतर्गत रानी कुहल सिंचाई योजनाओं का दौरा किया। टीम ने इन योजनाओं के लाभार्थियों से विस्तृत चर्चा की और उनका फोडबैक लिया। जिसमें विचित्र सिंह, भरत लाल, पूर्णिमा देवी, मनोहर, प्रभाकर, सुषमा देवी इत्यादि किसान शामिल हुए और सिंचाई सुविधाओं सिंचाई एवं अन्य प्रसार गतिविधियों के लाभों पर फीडबैक लिया। किसानों ने बताया कि इन योजनाओं से उनकी कृषि उत्पादकता में वृद्धि हुई है, उनकी आय में सुधार हुआ है और उनके जीवन स्तर में सकारात्मक बदलाव आए हैं। विशेषज्ञ टीम ने पपरोला और भटू में स्थित कलेक्शन सेंटरों का भी दौरा किया, जिन्हें किसान उत्पादक कंपनियों (एफपीसी) द्वारा संचालित किया किया जा रहा। इन केंद्रों ने किसानों को बेहतर बाजार जोडने की सुविधा प्रदान की है, जिससे उन्हें अपने उत्पादों के लिए उचित मूल्य मिल रहा है। टीम ने इन एफपीसी के संचालन को समीक्षा की और संबंधित किसानों से उनकी अनुभवों के बारे में बातचीत की। इसके अतिरिक्त, टीम ने पालमपुर में स्थापित शिटाके प्रशिक्षण और खेती केंद्र का भी निरीक्षण किया। यह परियोजना के पहले चरण के अंतर्गत स्थापित किया गया था। टीम ने वहां चल रही गतिविधियों का अवलोकन किया और किसानों को शिटाके मशरूम की खेती और नवाचार कृषि तकनीकों के प्रति प्रोत्साहित करने में केंद्र के योगदान की सराहना की। यह मूल्यांकन दौरा हिमाचल प्रदेश फसल विविधीकरण प्रोत्साहन परियोजना (चरण 1) परियोजना के दीर्घकालिक प्रभाव को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इस परियोजना ने सतत कृषि और ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कृषि विभाग से रजनीश शर्मा, अमित भूषण, सपन ठाकुर, विवेक कंवर और अन्य प्रसार अधिकारी भी विशेषज्ञ टीम के साथ उपस्थित रहे। विशेषज्ञ टीम के द्वारा जिला परियोजना प्रबंधक, मंडी, खंड परियोजना प्रबंधक, मंडी और उपस्थित अधिकारियों के साथ से बैठक का आयोजन किया गया। इसके उपरांत सिंचाई परियोजना कुंडला से सेगलि रोपा, उठाऊ सिंचाई परियोजना तकवाड़ और उखला का दौरा किया, लाभार्थी किसानों और कृषक विकास संघों के सदस्यों से विस्तृत चर्चा की गई। इसके साथ ही रिटेल आउट लेट सुन्दर नगर का भी दौरा किया गया।

एसपीएमयू में परियोजना निदेशक के नेतृत्व में जायका डेलिगेटस के साथ मीटिंग का आयोजन

जायका डेलिगेटस जिला परियोजना प्रबंधन इकाई पालमपुर के दौरे पर

जायका डेलिगेटस खण्ड परियोजना प्रबंधन इकाई हमीरपुर सिंचाई योजना बलेटा में दौरे पर।

जायका डेलिगेटस जिला परियोजना प्रबंधन इकाई मण्डी के दौरे पर

''स्वस्थ भोजन को है उगाना, अपने कल को है उज्जवल बनाना''

जिला परियोजना प्रबंधन इकाई मंडी के बढ़ते कदम, 19 सिंचाई परियोजना को किया पूरा

मण्डी। जिला परियोजना प्रबंधन इकाई, मंडी ने अब तक 74 एसडीपी तैयार कर ली हैं और 65 एसडीपी को किसान विकास संघ द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है। इन 65 में से 6 एसडीपी को जनवरी महीने में अनुमोदित किया गया।

खंड परियोजना प्रबंधन इकाई, सरकाघाट द्वारा 15 जनवरी 2025 को जिला परियोजना प्रबंधक, मंडी की उपस्थिति में एफआईएस घुलाणु को स्थानीय किसान विकास संघ को आगे के संचालन और रखरखाव के लिए सौंपा गया, इस सिंचाई परियोजना का कुल कमांद क्षेत्र लगभग 7.36 हेक्टेयर है इसके बनने से 56 किसान परिवार लाभान्वित होंगे। इस सिंचाई परियोजना में एक बुनियादी इंजीनियरिंग कौशल शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें किसानों को सिंचाई योजना के संचालन और रखरखाव के बारे में जानकारी दी गई।

खंड परियोजना प्रबंधन इकाई, मंडी द्वारा सियां री कुहल का निर्माण करवाकर इसको भी दिनांक 22 जनवरी 2025 को स्थानीय किसान विकास संघ को सौंप दिया, इस सिंचाई परियोजना के निर्माण में लगभग 51 लाख रूपये का खर्चा हुआ जिससे 600 मीटर मुख्य कुहल और 900 मीटर जल वितरण कूहलों का निर्माण करवाया गया। इसके बनने से 70 लाभार्थी परिवारों की 25. 39 हेक्टर भूमि में पानी की सुविधा हुई। अब तक जिला परियोजना प्रबंधन इकाई, मंडी के द्वारा 10 सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण कार्य पूरा करके स्थानीय किसान विकास संघों को सौंप दिया है।

जिला परियोजना प्रबंधन इकाई, मंडी के अंतर्गत आने वाले खंड परियोजना प्रबंधन इकाई, कुल्लू के द्वारा 60 प्रतिभागियों को पालमपुर कृषि विश्वविद्यालय के सब्जी फार्म, सोयाबीन प्रसंस्करण इकाई, कृषि संग्रहालय, कृषि प्रौद्योगिकी सूचना केंद्र और सीएसआईआर-आईएचबीटी में किसानों का भ्रमण करवाया ताकि किसान खेती करने के नये गुर सिख कर उनको अपने खेतों में अपनायें ताकि उनको आर्थिकी में लाभ हो सके। पीएमसी विशेषज्ञों द्वारा इस माह जिला परियोजना प्रबंधन इकाई, मंडी के अंतर्गत आने वाली विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं का दौरा जैसे एफआईएस खारखान खाद-लेहोटी, एफआईएस सुरथी-थाची, एफआईएस दधानाल्लाह-कोट, एलआईएस कोटलू , एफआईएस थारस, एफआईएस नरैनी और एफआईएस ब्रान बिहाल सेरी, इन परियोजनाओं में किये जा रहे निर्माण कार्यों का जायजा लिया गया ताकि निर्माण कार्यों में कोई भी कोताही न बरती जाए और समय पर इन सिंचाई परियोजनाओं का कार्य पूरा हो सके।

जिला परियोजना प्रबंधक, मंडी के द्वारा इस माह लिफ्ट सिंचाई योजना योह का दौरा किया जिसमें सम्बंधित ठेकेदार को हिदायत दी गई कि इसको समय पर निर्माण कार्य पूरा किया जाए और निर्माण में कोई भी त्रुटि न हो इसके साथ ही मुख्य वितरण टैंक और भंडारण टैंक के हो रहे कार्यों का जायजा लिया गया।

बीपीएमयू मण्डी की बहाव सिंचाई योजना खलगवाड़ नाला से टिकरु।

बीपीएमयू कुल्लू की बहाव सिंचाई योजना नैरणी।

बीपीएमयू गोहर की बहाव सिंचाई योजना बधारनु गिरझनु

जिला परियोजना प्रबंधन इकाई, पालमपुर के अंतर्गत चल रहे कार्य: एक नजर

पालपमुर। जिला परियोजना प्रबंधन इकाई, पालमपुर के अंतर्गत खंड परियोजना प्रबंधन इकाई, धर्मशाला के द्वारा एफआईएस त्रैम्बला कूहल का निर्माण कार्य पूरा करवाया, जिसका कमांद क्षेत्र 17.59 हेक्टेयर और इसके बनने से 85 परिवारों को लाभ मिलेगा और इसके निर्माण पर लगभग 42 लाख रुपये की लागत आई है। इस सिंचाई परियोजना का हस्तांतरण 28 जनवरी, 2025, को हिमाचल प्रदेश सरकार के उप मुख्य सचेतक श्री केवल सिंह पठानिया की उपस्थिति में कृषक विकास संघ को सौंपा गया। जिला परियोजना प्रबंधन इकाई, पालमपुर में अब तक कुल 69 एसडीपी तैयार कर ली हैं। यह एसडीपी वर्तमान में संबंधित केवीए द्वारा समीक्षा और अनुमोदन के अधीन हैं। इस माह में 11 एसडीपी को केवीए अनुमोदन प्राप्त किया है। बीपीएमयू धर्मशाला के तहत विभिन्न उप-परियोजनाओं के किसानों के लिए 15 से 20 जनवरी, 2025 तक शिताके की खेती पर छह दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसके बाद 21 से 22 जनवरी, 2025 तक शिताके मशरूम के कटाई उपरांत प्रबंधन पर दो दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया। 28 जनवरी 2025 को बीपीएमयू धर्मशाला के संबंध में एफआईएस नन्हियां कुहल में नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया जिसमें किसानों को परियोजना में चल रही विभिन्न गतिविधियों की जानकारी दी गई।

जिला परियोजना प्रबंधन इकाई, पालमपुर के विभिन्न खंड परियोजना प्रबंधन इकाइयों में चल रहे निर्माण कार्यों का पीएमसी विशेषज्ञों के द्वारा साइटों का दौरा किया, जिसमें खंड परियोजना प्रबंधन इकाई, पालमपुर के तहत एफआईएस गर्टुहल, एफआईएस कटुहल, एफआईएस दादुल और वीएमएफ भट्टू, खंड परियोजना प्रबंधन इकाई, धर्मशाला के तहत एफआईएस रिदुआन कूहल और एफआईएस त्रैम्बला कूहल और खंड परियोजना प्रबंधन इकाई, चंबा के तहत एफआईएस सारुल, एफआईएस ओसलजमुरा, एफआईएस संघनी और एफआईएस मेरु शामिल हैं।

जिला परियोजना प्रबंधन इकाई, पालमपुर में जायका विशेषज्ञ श्री तोमू शिकिदा और सुश्री काओरी ओसाने ने हिमाचल प्रदेश फसल विविधीकरण संवर्धन परियोजना (चरण-1) का मूल्यांकन करने के लिए कांगड़ा जिले का दौरा किया। कृषि विभाग द्वारा 2011 से 2020 तक कार्यान्वित की गई इस परियोजना का उद्देश्य सिंचाई सुविधाओं को बढ़ाना और किसानों पर उनके सामाजिक-आर्थिक प्रभाव का आंकलन करना था। अपने दौरे के दौरान, टीम ने विभिन्न सिंचाई योजनाओं का निरीक्षण किया और बीपीएमयू पालमपुर, देहरा और धर्मशाला के तहत किसानों से बातचीत की। विशेषज्ञों ने चरण-1 के तहत निर्मित और अब किसान उत्पादक कंपनियों (एफपीसी) द्वारा प्रबंधित पपरोला और भट्टू में संग्रह केंद्रों की भी समीक्षा की, जिससे बाजार संपर्क बढ़ा है और किसानों के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित हुआ है। इसके अतिरिक्त, टीम ने पालमपुर में शिताके प्रशिक्षण और खेती केंद्र का दौरा किया, और शिताके की खेती और नवीन कृषि तकनीकों को बढ़ावा देने में इसकी भूमिका को स्वीकार किया।

जायका डेलिगेटस कोलेक्शन सेंटर पपरोला (पालमपुर) का दौरा करते हुए।

खंड परियोजना प्रबंधन इकाई धर्मशाला की बहाव सिंचाई योजना सल्ली भलेड़ कूहल का निरीक्षण करते हुए।

शिटाके कल्टीवेशन ट्रेनिंग सेंटर (पालमपुर) में के किसानों के लिए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन

नुक्कड़ नाटकों से दी प्रोजेक्ट गतिविधियों की जानकारी

बिलासुपर। हिमाचल प्रदेश फसल विविधीकरण प्रोत्साहन परियोजना-2 के तहत खंड परियोजना प्रबंधन इकाई, बिलासपुर की ओर महासंगम थिएटर ग्रुप बिलासपुर के कलाकारों द्वारा छः उठाऊ सिंचाई परियोजनाओं (भक्तपुर, बेहरन झरेडी, सुसनाल, भपराल, तरोंतरा और छकोह) में नुक्कड़ नाटकों का आयोजन 20 जनवरी से 22 जनवरी तक किया गया। इस दौरान किसानों को नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से जायका परियोजना के उद्देश्यों और फसल विविधीकरण के महत्व के बारे में जागरूक किया गया। नुक्कड़ नाटकों की मदद से न केवल किसानों को अपनी स्थानीय भाषा में सभी गतिविधियों को समझने में सहायता मिलती है बल्कि इसके इलावा उपस्थित अधिकारी के द्वारा किसानों की सभी शंकाओं का निवारण मौके पर करके उनको प्रोत्साहित भी किया जाता है, ताकि किसान सभी बातों को समझ कर अपने लिए योजनाओं का चयन करके अपनी आर्थिकी में वृद्धि कर सके।

इस दौरान इन सिंचाई परियोजनाओं में खंड परियोजना प्रबंधक डॉ. देवेंद्र सांख्यान, और परियोजना से जुड़े हुए अधिकारीगण और कृषक विकास संघ के प्रबंधन समिति के सदस्य मौजूद रहे।

बीपीएमयू बिलासपुर के एलआईएस सुसनाल में नुक्कड़ नाटक का किया आयोजन

गधीमण-मझोठी सिंचाई परियोजना का कार्य पूरा अन्य गतिविधियां कर रहे हैं लागू

गोहर। सिंचाई परियोजना गधीमण -मझोठी का निर्माण कार्य को पूरा करके इस सिंचाई योजना को कृषक विकास संघ को सौंप दिया गया है। इस सिंचाई परियोजना का कुल कमांद क्षेत्र लगभग 14.91 हेक्टर और 168 लाभार्थी किसान परिवारों को इसके बनने से लाभ हुआ है, जहां पहले किसान ज्यादातर परम्परागत फसलें (गेहूं, मक्की और धान) ही उगाते थे अब वह सब्जियों की तरफ अपना रुझान दिखा रहे हैं। इसी को देख कर परियोजना के अधिकारियों ने इस क्षेत्र को मॉडल स्थल के रूप में चिन्हित किया गया। इसके लिए परियोजना की तरफ से चलाई जा रही गतिविधि पी.एम.वी.आर.पी. और एस.एच.ई.पी. पहलों के अंतर्गत भी शामिल किया गया है। किसानों के प्रोत्साहन के लिए इस क्षेत्र के 1 हेक्टेयर भूमि में मटर की फसल का प्रदर्शन प्लाट भी लगाया है जिससे किसान मटर की खेती के बारे में और अधिक सीख सकें जैसे पंक्तियों में मटर लगाने के क्या फायदे हैं, बीज की मात्रा के बारे, दवाइयों का छिड़काव, मटर में कौन-कौन बीमारियां आती हैं उनका निवारण कैसे करना है ये सब किसानों को परियोजना के अधिकारियों द्वारा समय-समय पर प्रदर्शन प्लाट में जाकर समझाया जाता है। इन गतिविधियों का एक मात्र उद्देश्य है कि किसान परियोजना से पूरा लाभ लेकर अपनी आय को बढ़ा सकें।

बीपीएमयू गोहर की बहाव सिंचाई योजना गधिमन मझोठी में लगाए प्रदर्शन प्लॉट

खंड परियोजना प्रबंधन इकाई ऊना ने दिया प्रशिक्षण

ऊना, हिमाचल प्रदेश फसल विविधीकरण प्रोत्साहन परियोजना जायका चरण - 2 के अंतर्गत खंड परियोजना प्रबंधन इकाई ऊना द्वारा एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर उप परियोजना बबेहड़ में 35 किसानों ने भाग लिया।

कृषि प्रसार अधिकारी वीर विवेक सिंह द्वारा किसानों को गृह वाटिका में प्याज की पनीरी आधुनिक तकनीक से लगाने की प्रक्रिया किसानों के साथ सांझा की तथा जायका परियोजना में फसल प्रबंधन व परियोजना का रिकॉर्ड बनाने व संभालने का प्रशिक्षण प्रदान किया। किसानों ने जायका परियोजना का आभार व्यक्त किया व परियोजना की सफलता में योगदान देने का आश्वासन दिया।

बीपीएमयू ऊना के बबेहड़ में एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित

प्राकृतिक खेती है खुशहाल जीवन का आधार

माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का ये एलान कि प्रदेश के सभी कृषि फार्मों में प्राकृतिक खेती की जाएगी, जायका कृषि परियोजना प्रेरणास्त्रोत है। मुख्यमंत्री की इस सोच को हमने साकार रूप दिया है, जब उन्होंने 2024 के आरंभ में प्रोजेक्ट समीक्षा बैठक में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के निर्देश दिये थे। जायका परियोजना ने खरीफ मौसम, 2024 में 517 बीघा भूमि में फिंगर मिल्लेट्स की खेती अपने विभिन्न उप परियोजना के लाभार्थी किसानों के खेतों में प्रदर्शन प्लाट लगवाकर करवाई ताकि किसान इसकी खेती के बारे में सीख सकें और उस अनाज का उपयोग अपने खाने के साथ-साथ अगले साल के लिए अपना खुद का बीज रख सकें। इसके अतिरिक्त, जायका कृषि परियोजना ने सुन्दरनगर के 'लाइव किचन' प्राकृतिक खेती उत्पादन का ही प्रयोग किया जा रहा है।

ई-पत्रिका के इस अंक में हम प्राकृतिक खेती प्रदेश सरकार की नीति और इसके लिए उपयोगी अदानों को बनाने की विधि भी बता रहे हैं। किसान अपने घर में इन सभी दवाइयों और खादों को बनाकर अपनी फसलों में इसका उपयोग करें ताकि किसान महंगी रासायनिक खादों और रासायनिक दवाइयों का उपयोग कम से कम करें जिससे पैसों के साथ-साथ अपने स्वास्थ्य और भूमि, वातावरण और जल में पड़ने वाले दुष्प्रभावों से खुद को बचा सके।

हिमाचल प्रदेश सरकार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए गांव-गांव में किसानों के लिए प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन कर रही है। इसका अनुसरण करते हुए जायका कृषि परियोजना की ओर से सभी प्रसार अधिकारियों को हिदायतें दी गई हैं कि वो भी परियोजना के लाभार्थी किसानों को अपने प्रशिक्षण शिविरों में प्राकृतिक खेती करने लिए जागरूक करें ताकि जायका कृषि परियोजना भी प्रदेश सरकार की नीतियों को बढ़ाने में एक योगदानकर्ता की भूमिका निभाकर किसान परिवार की आय में वृद्धि करके, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए अपनी आहुति प्रदान कर सकें।

एक बार फिर से नववर्ष की मंगलमय शुभ कामनाओं सहित।

डॉ. सुनील चौहान
परियोजना निदेशक
एवं प्रधान सम्पादक

उठाऊ सिंचाई परियोजना छकोह का कार्य प्रगति पर : डॉ. देवेन्द्र सांख्यान

बिलासपुर। फसल विविधीकरण प्रोत्साहन परियोजना जायका चरण-2 के अंतर्गत बन रही उठाऊ सिंचाई परियोजना छकोह का निर्माण कार्य प्रगति पर है इसका निर्माण खंड परियोजना प्रबंधन इकाई, बिलासपुर के द्वारा करवाया जा रहा है। सिंचाई परियोजना का कार्य पूर्ण होने पर 74 किसान परिवार की लगभग 17. 55 हेक्टयर भूमि को पानी मिलेगा। इस परियोजना के निर्माण में लगभग 70.54 लाख खर्च होंगे। अब तक यहां के किसान परम्परागत खेती करके अपने जीवन का निर्वहन कर रहे हैं इसके बनने से सब्जियों का उत्पादन करके ये भी अपनी आर्थिकी को सुदृढ़ कर सकेंगे। इस उठाऊ सिंचाई परियोजना का मुख्य टैंक, मेन लाइन, पम्प हाउस व डायवर्सन वियर का कार्य पूर्ण होने को है और साथ में ही बिजली कनेक्शन का कार्य भी प्रगति पर है। खण्ड परियोजना प्रबंधक बिलासपुर डॉ. देवेन्द्र सांख्यान ने परियोजना का दौरा दिनांक 28 जनवरी 2025 को किया और निर्देश दिया कि परियोजना का कार्य अति शीघ्र पूर्ण करें, ताकि इस सिंचाई परियोजना को जल्दी किसानों को सौंप कर परियोजना की अगली गतिविधियों को यहां लागू किया जा सके।

प्राकृतिक खेती में प्रयोग होने वाले घटक

बीजामृत कैसे बनाएं :-

यह किसी भी प्रकार के बीज, पौध तथा कंद को पौध जनित रोगों से बचाता है। यह बीजों के उगने की संभावना को बढ़ाता है तथा पौधों को शुरूआती अवस्था में होने वाले रोगों एवं कीड़ों से बचाकर उनका संरक्षण करता है।

क्र. सं.	सामग्री	मात्रा
1.	पानी	4 लीटर
2.	गौमूत्र	1 लीटर
3.	गोबर	1 कि.ग्रा
4	चूना	10 ग्राम
5	खेत की मेढ़ या जंगल की मिट्टी	50 ग्राम (1 मुट्ठी)

विधि :- इन सभी सामग्रियों को अच्छी तरह से ड्रम में घोलें। इस घोल को 24 घंटे बोरी से ढककर छांव में रखने के बाद बीजों को भिगोएं। ध्यान रहे इस दौरान इस घोल को सुबह शाम 2-2 मिनट घोलना है।

याद रखें :- बुआई से 24 घंटे पहले बीजों को बीजामृत में अच्छी तरह भिगोना चाहिए। बीजामृत का प्रयोग निर्माण के 2 दिन के भीतर करें।

जीवामृत कैसे बनाएं :-

जीवामृत असंख्य लाभदायक सूक्ष्म जीवाणुओं का भंडार है। इससे फसलों को सभी आवश्यक पोषक तत्व आसानी से मिल जाते हैं। साथ ही यह एक अच्छा फफूंदनाशक भी है। इसे तैयार होने में गर्मियों में 3-6 दिन व सर्दियों में 7-14 दिन लगते हैं। तैयार होने के बाद इसे 15 दिनों के भीतर प्रयोग कर लेना चाहिए। हर 21 दिन के बाद 1 बीघा भूमि पर 40 लीटर जीवामृत का छिड़काव अच्छा माना गया है।

क्र. सं.	सामग्री	मात्रा
1.	पानी	180 लीटर
2.	गौमूत्र	10 लीटर
3.	गोबर	10 कि.ग्रा
4.	गुड़ या मीठे फलों का गूदा	1.5 कि.ग्रा
5.	खेत की मेढ़ या जंगल की मिट्टी	50 ग्राम (1 मुट्ठी)
6.	बेसन या किसी भी दलहन 5 का आटा	1.5 कि.ग्रा

जीवामृतः एक एकड़ (5 बीघा / 10 कनाल) भूमि के लिए

विधि : इन सभी सामग्रियों को अच्छी तरह से ड्रम में घोलें, घोल को घड़ी की सुई की दिशा में 2-3 मिनट तक घोलें। ड्रम को बोरी से ढक कर 72 घंटे तक छाया में रख दें। सुबह-शाम 2-2 मिनट घोलें। इस घोल का उपयोग 15 दिन के अन्दर करें।

घनजीवामृत कैसे बनाएं :-

यह जीवामृत का ही ठोस रूप है। चूंकि हमारी ज्यादातर भूमि सिंचाई के बिना है ऐसे में घनजीवामृत का इस्तेमाल कर बेहतर फसल ली जा सकती है।

क्र. सं.	सामग्री	मात्रा
1.	गौमूत्र	आवश्यकतानुसार
2.	गोबर	200 कि.ग्रा
3.	गुड़ या मीठे फलों का गूदा	1 कि.ग्रा
4.	खेत की मेढ़ या जंगल की मिट्टी	50 ग्राम (1 मुट्ठी)
5.	बेसन या किसी भी दलहन 5 का आटा	1 कि.ग्रा

1 एकड़ (5 बीघा/10 कनाल) भूमि के लिए

विधि-गाय के गोबर को किसी पक्के फर्श पर फैलाएं फिर इसके बाद गुड़ या फलों का गूदा व बेसन डालें। अब मेढ़ की मिट्टी के साथ आवश्यकतानुसार गौमूत्र भी मिला लें। अब सभी सामग्रियों को फावड़े से मिलाएं। इसे 2-4 दिन तक छायादार स्थान में सुखाएं। अच्छी तरह सुखाने और बारीक करने के बाद खेत में उपयोग करें। इसका उपयोग एक साल तक किया जा सकता है।

दरेकास्त्र कैसे बनाएं :-

फल व सब्जियों में रस चूसने वाले कीटों और छोटी इरिलयों की रोकथाम के लिए दरेकास्त्र का प्रयोग किया जाता है।

क्र. सं.	सामग्री	मात्रा
1.	दरेक या अन्य स्थानीय पौधों (बणा, बरवा, भांग, बिच्छू यूटी, अरंडी, लेटाना, ऐलुआंया या अन्य कड़वे पौधे, जिन्हें गाय न खाती हो)	2 कि.ग्रा
2.	गौमूत्र	2 लीटर
3.	गोबर	40 कि.ग्रा
4.	पानी	40 लीटर

एक बीघा के लिए सामग्री

विधि : एक ड्रम में 40 लीटर पानी, दरेक या अन्य स्थानीय पौधों (बणा, बरवा, भांग, बिच्छू यूटी, अरंडी, लेटाना, ऐलुआंया या अन्य कड़वे पौधे, जिन्हें गाय न खाती हो) की टहनियों उपरोक्त अन्य सामग्री मिला लें। सुबह-शाम घड़ी की सूई की दिशा में इस मिश्रण को 2-3 मिनट तक घोलें। आम वातावरण में 2 दिन व शीतकाल में सप्ताह में यह तैयार हो जाता है। कपड़े से छान कर 40 लीटर दरेकास्त्र (बिना पानी मिलाए) 1 बीघा में छिड़काव कर सकते हैं।

ब्रह्मास्त्र कैसे बनाएं :-

यह बड़ी सूंडियों/इल्लियों से फसल सुरक्षा के लिए उपयोग किया जाता है।

क्र.सं.	सामग्री	मात्रा
1.	गौमूत्र	50 लीटर
2.	(अ) आम, अमरूद या अरंडी के पत्तों की चटनी (आ) स्थानीय उपलब्ध पौधों में से किन्ही दो के पत्तों की चटनी	3-3 कि.ग्रा प्रति पौधा

एक बीघा के लिए सामग्री

विधि : पत्तों की चटनी की गौमूत्र में डालकर धीमी आंच पर एक उबाल आने तक गर्म करें। 48 घंटे तक ठंडा होने के लिए रख दें। 50 लीटर घोल को 40 लीटर पानी में मिलाकर प्रति बीघा फसल घर छिड़काव करें। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग 6 माह तक किया जा सकता है।

खट्टी लस्सी

फफूंद नियंत्रण और पौधों व फसलों की इम्यूनिटी को बढ़ाने में सहायक है। इसके छिड़काव से एंटीबॉडीस तैयार होते हैं।

क्र. सं.	सामग्री	मात्रा
1.	पानी	40 लीटर
2.	खट्टी लस्सी (4 से 5 दिन पुरानी)	1 लीटर

एक बीघा के लिए सामग्री

विधि : पानी व खट्टी लस्सी को अच्छी प्रकार से मिलाकर 1 बीघा में छिडकाव करें।

अग्नि-अस्त्र कैसे बनाएं :-

रस चूसने वाले कीड़े, छोटी सुंडी/ इल्लियों के लिए उपयोगी

एक बीघा के लिए सामग्री

क्र. सं.	सामग्री	मात्रा
1.	नीम / दरेक के पत्ते	1 किलोग्राम
2.	गौमूत्र	4 लीटर
3.	तम्बाकू पाउडर	100 ग्राम
4.	तीखी हरी मिर्च की चटनी	100 ग्राम
5.	देशी लहसुन की चटनी	100 ग्राम

एक बीघा के लिए सामग्री

विधि : कटे हुए नीम/दरेक के पत्तों को, तम्बाकू पाउडर, मिर्च की चटनी व लहसुन की चटनी को गौमूत्र में मिलाकर धीमी आंच पर उबाल लें। मिश्रण को 48 घंटे के लिए रख दें व इस मिश्रण को सुबह-शाम लकड़ी की डंडी के साथ घोलें। मिश्रण का 12-16 लीटर घोल 40 लीटर पानी में मिलाकर 1 बीघा की फसल पर छिडकाव करें। इसको 3 महीने के भीतर उपयोग कर लेना चाहिए।

पौध मलहम/तना लेप/पौध पेस्ट :-

यह पौधे के तने को कीटों व कवक के प्रकोप से बचाता है।

क्र. सं.	सामग्री	मात्रा
1.	पानी	5 लीटर आवश्यकतानुसार
2.	गौमूत्र	5 लीटर आवश्यकतानुसार
3.	गोबर	ताजा गोबर 20 कि.ग्रा
4.	दरेक या अन्य स्थानीय पौधों (जिन्हें गाय न खाती हो)	10 कि.ग्रा
5.	हल्दी	250 ग्राम
6.	हींग पाउडर	40 ग्राम
7.	चिकनी मिटटी + अलसी का तेल	2.5 कि.ग्रा +1 लीटर

विधि : एक ड्रम में 10 लीटर पानी, 20 लीटर गौमूत्र और 20 किलोग्राम गोबर डालें। इसके बाद दरेक या अन्य उपलब्ध पौधे जिन्हें गाय न खाती हो के पत्तों की 10 किलोग्राम चटनी (सिलबट्टे से पिसी हुई) व बाकि सामग्री को क्रमशः डाल दें। अब इसे लकड़ी के डंडे से घोलें ताकि सभी घटक अच्छे से आपस में मिल जाएं। ड्रम को 24 घंटे के लिए जूट की बोरी से ढक कर रख दें । इसके तैयार होने के बाद इसे लगाने से पहले अलसी का तेल मिलायें।

दशपर्णी अर्क कैसे बनाएं :-

यह सभी तरह के रस चूसक कीट और इल्लियों के नियंत्रण के लिए प्रयोग में लाया जाता है।

क्र. सं.	सामग्री	मात्रा
1.	पानी	175 लीटर
2.	गौमूत्र	20 लीटर
3.	गोबर	2 कि.ग्रा
4.	करज, अरंड, सीताफल, बेल, गेंदा, तुलसी,धतूरा आम, आक आदि के पत्ते (जिन्हें गाय न खाती हो)	2 से 2.5 कि.ग्रा
5.	तीखी हरी मिर्च	1 कि.ग्रा
6.	अदरक की चटनी	500 ग्राम
7.	देसी लहसुन की चटनी	1 कि.ग्रा
8.	हल्दी पाउडर	500 ग्राम
9.	हींग पाउडर	40 ग्राम
10.	सौंठ पाउडर	200 ग्राम
11.	तम्बाकू का पाउडर	200 ग्राम
12.	नीम / दरेक के पत्ते	5 कि.ग्रा

विधिः गोबर व गौमूत्र को पानी में अच्छी प्रकार घोलकर 2 घंटे के लिए रख दें। हल्दी का पाउडर, अदरक की चटनी में हींग पाउडर को अच्छी प्रकार मिलाकर 24 घंटे के लिए छाया में रखें। इस मिश्रण को हिलाते हुए इसमें सौंठ पाउडर, तम्बाकू का पाउडर, तीखी मिर्च व देसी लहसुन अच्छी प्रकार मिलाकर 24 घंटे की लिए रख दें। पौधों के पतों को इस मिश्रण में दबा दें। मिश्रण को बोरी से ढककर 30-40 दिन के लिए रख दें इस घोल को सुबह शाम डंडे की सहायता से हिलाते रहें। 30 से 40 दिनों के बाद ये अर्क फसल में उपयोग करने लायक हो जाता है। अतः 6 से 8 लीटर अर्क को 175 लीटर पानी में मिलाकर 5 बीघा की फसल के हिसाब से छिड़काव करें। दशपर्णी अर्क का छिड़काव दोपहर के बाद करने से अधिक लाभ मिलता है। दशपर्णी अर्क को घोलते समय नाक पर रूमाल जरूर रख लें। दशपर्णी अर्क बनाने के दौरान तथा भंडारण के समय दशपर्णी अर्क को बच्चों तथा पशुओं इत्यादि की पहुंच से दूर रखें।

सप्त धान्यांकुर अर्क कैसे बनाएं :-

इसमें सात प्रकार के अनाजों का प्रयोग किया जाता है। इसके छिड़काव से फलों के पौधों में फलों की संख्या में बढ़ोतरी व फसल में दानों की मात्रा में बढ़ोतरी होती है। दानों और फलों में चमक आती है, उनका भार बढ़ता और सुगन्ध भी बढ़ती है। यह एक तरह से ग्रोथ रेगुलेटर और प्रतिरक्षा कवच की तरह काम करता है। इसका प्रयोग तैयार होने के दो दिन के भीतर करें।

क्र. सं.	सामग्री	मात्रा
1.	तिल (काले)	100 ग्राम
2.	मूंग, उड़द, लोबिया, मोठ और चने	100-100 ग्राम प्रत्येक
3.	गेहूं	100 ग्राम
4.	पानी	195 लीटर
5.	गौमूत्र	5 लीटर

विधि- एक कटोरी में तिल के बीजों को पानी में मिलाकर रातभर के लिए भिगोकर रखें। दूसरे दिन तिल, मूंग, उड़द, लोबिया, मोठ, चने और गेहूं मिलाकर रातभर के लिए पानी में भिगोकर रख दें। तीसरे दिन सातों प्रकार के दानों को पानी से निकालकर एक पोटली में बांधकर घर के अंदर टांग दें व पानी को सुरक्षित रख दें।

फिर बीजों के अंकुरित होने के उपरान्त सभी बीजों को पीस कर चटनी की तरह बना लें। 195 लीटर जल, 5 लीटर गौ मूत्र व बीजों से सुरक्षित पानी मिलाकर एक मिश्रण तैयार करें।

इसमें हाथों की सहायता से सातों प्रकार के बीजों की चटनी को लकड़ी के डंडे की सहायता से मिला दें।

घोल तैयार होने के बाद इसको बोरी से ढककर दो घंटे तक रख दें। दो घंटे के बाद फिर इसको कपड़े से छान लें। इस प्रकार सप्त धान्यांकुर अर्क उपयोग के लिए तैयार है।

विशेष इस अर्क को 48 घंटे के अंदर-अंदर उपयोग करें।

फसल में उपयोग-

1) दानों की दुग्धावस्था में।
2) बाल्यावस्था (छोटी फलियों) में।
3) फूलों की फसल में, कली अवस्था में करें।

लाभ : 1) सप्त धान्यांकुर अर्क छिड़कने से दानों पर चमक आती है।
2) फलों का गिरना बन्द होता है।
3) फली में दाने पूरे भरते हैं।
4) दानों का आकार व भार बढ़ता है।
5) दानों में सुगन्ध बढ़ती है।
6) प्राकृतिक आपदाओं को सहन करने की शक्ति बढ़ती है।

स्त्रोत : आतमा परियोजना

प्राकृतिक खेती के लिए सरकार के प्रयास

हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से किसानों को प्राकृतिक खेती करने के लिये प्रोत्साहित करने के साथ-साथ किसानों के लिये बहुत सी योजनाओं को भी लागू किया है जैसे प्राकृतिक खेती में प्रयोग होने वाले आदान बनाने के लिए ड्रम खरीद पर अधिकतम 2,250 रूपये (रूपये 750/- प्रति ड्रम एवं अधिकतम 3 ड्रम/ प्राकृतिक खेती किसान परिवार के लिए) अनुदान का प्रावधान।

गौशाला के फर्श को पक्का कर गोमूत्र इकट्ठा करने के लिए गड्ढा बनाने हेतु अधिकतम 8000 रूपये प्रति प्राकृतिक खेती किसान के लिये दिए जाने का प्रावधान।

भारतीय नस्ल की गाय की खरीद पर 50 प्रतिशत उपदान और अधिकतम 25000/- रूपये उपदान का प्रावधान है तथा गाय को लाने के लिए भाड़ा भी दिया जाता हैं जोकि 5 हजार अतिरिक्त होगा। प्राकृतिक खेती में काम आने वाले आदानों की आपूर्ति हेतु प्रत्येक गांव में प्राकृतिक खेती संसाधन भण्डार खोलने के लिए 10,000/- रूपये तक की सहायता राशि प्रदान करने का प्रावधान है। जो भी किसान को प्राकृतिक खेती करने का इच्छुक है वो अपने खंड के कृषि विभाग के आतमा परियोजना में कार्यरत खण्ड तकनीकी प्रबंधक (बीटीएम) या सहायक तकनीकी प्रबंधक (एटीएम) से मिलकर अपने घर द्वार में इसका प्रशिक्षण ले सकता है। वह अधिकारी अगले छः महीने तक आपके खेत में लगे प्रदर्शन प्लाट में सभी आदानों को बनाकर उसका कैसे और कब उपयोग करना है उसकी पूरी जानकारी देगा।

''स्वस्थ भोजन को है उगाना, अपने कल को है उज्जवल बनाना''

सैंज किरटी कूहल का लोकार्पण, 13.8 हेक्टेयर कृषि क्षेत्र होगा सिंचित, करीब 48 परिवारों का होगा फायदा

रामपुर। हिमाचल प्रदेश फसल विविधीकरण प्रोत्साहन परियोजना जायका चरण 2 के रामपुर इकाई के अंतर्गत बन रही कूहल का निर्माण कार्य पूरा होने पर उसे गांव के किसानों को सौंप दिया गया। 25 लाख की लागत से बनी 2200 मीटर लंबी कूहल से कृषि का लगभग 13.79 हैक्टेयर क्षेत्रफल सिंचित होगा और इससे 46 के करीब किसान लाभांवित होंगे।

कूहल को किसानों को सौंपने के बाद कृषक विकास संघ सैंज इसकी देखरेख करेगा।

इस मौके पर खंड परियोजना प्रबंधक डॉ. प्रवीण अत्री, कृषि विशेषज्ञ वरुण शर्मा, कूहल निर्माण अभियंता उपांशु शर्मा, कनिष्ठ अभियंता सक्षम शर्मा व सर्वेक्षक विक्रांत राणा उपस्थित थे। वहीं किसानों ने हिमाचल प्रदेश सरकार के जायका परियोजना का आभार व्यक्त किया।

बहाव सिंचाई योजना के तहत हरे-भरे होंगे 238 किसानों के खेत

पिछला डियूर व कंधवारा पंचायत में 6 माह में पूरा होगा 4 किलोमीटर कूहल का कार्य

चम्बा। जायका परियोजना के तहत खंड चम्बा के उपमंडल सलूणी की पिछला डियूर व कंधवारा पंचायत के किसानों को आने वाले समय में जल्द ही सिंचाई सुविधा मिलेगी। पंचायतों के गुलेल व सैणी गांव में लाखों रुपए की लागत से बनने जा रही बहाव सिंचाई योजना के तहत दोनों पंचायतों के 238 किसानों को सिंचाई सुविधा मिलेगी। दोनों क्षेत्रों में गुलेल में 22.42 हैक्टेयर तथा सैणी में 18.92 हैक्टेयर भूमि में सिंचाई सुविधा मिलेगी। जायका परियोजना के तहत दोनों पंचायतों का 23 जनवरी को दौरा किया। इस मौके पर प्रगतिशील किसानों से मिलकर जापान की खेती की तकनी व अनुभव किसानों के साथ सांझा किए गए। इस मौके पर सिंचाई योजना के तहत कार्य करने के लिए ठेकेदार की टीम के साथ कृषक किसान संघ के सदस्य भी मौजूद रहे। योजना के तहत आगामी दिनों में दोनों पंचायतों के लिए कुल 3 किलोमीटर लंबी कूहल का कार्य शुरु कर दिया जाएगा, जिसके तहत कार्य शुरु किए जाएंगे।

इस कार्य के लिए आगामी 6 माह का समय निर्धारित किया गया है, जिसके बाद किसानों को लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। बीते काफी समय से उक्त क्षेत्र के किसानों द्वारा सिंचाई सुविधा मुहैया करवाने की मांग की जा रही थी, जिसके तहत जायका परियोजना के तहत कूहल कार्य शुरू करने की मांग ग्रामीणों द्वारा की गई।

उक्त क्षेत्र के अधिकतर लोग कृषि से जुड़े हैं तथा खेतीबाड़ी करके अपने परिवार का गुजारा करते हैं।

पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण यहां खेतीबाड़ी के लिए अधिकतर समय बारिश पर ही निर्भर होना पड़ता है। बारिश न होने के कारण कई बार किसानों की फसलें बर्बाद हो जाती हैं, जिससे उन्हें काफी नुकसान होता है, लेकिन अब सिंचाई सुविधा से जुड़ने के बाद ऐसा नहीं होगा, किसानों को पूरे 12 माह सिंचाई सुविधा मिलेगी।

जायका खंड परियोजना प्रबंधक इकाई चम्बा के प्रबंधक भानू प्रताप ने बताया कि पिछला डियूर व कंधवारा पंचायत को सिंचाई सुविधा से जोड़ने के लिए आगामी 4 माह का समय निर्धारित किया गया है। इस बारे में साइट का निरीक्षण किया गया। करीब 4 किलोमीटर कूहल के निर्माण होने के बाद दोनों पंचायतों के 238 किसानों के खेतों को सुविधा मिलेगी।

सिंया री कूहल किसानों को समर्पित

मंडी। हिमाचल प्रदेश फसल विविधीकरण परियोजना द्वितीय चरण के तहत खंड परियोजना प्रबंधक मंडी की ओर से बहाव सिंचाई योजना सिंया री कूहल किसानों को समर्पित कर दी। इस परियोजना के तहत 32 मीटर लंबे हेड वियर की मरम्मत करवाई गई। लगभग 600 मीटर लंबी मुख्य कूहल के साथ सिंचाई के लिए 900 मीटर जल वितरण कूहलों का निर्माण किया गया। खेतों की जुताई और कृषि उपकरण ले जाने के लिए ट्रैक्टर क्रॉसिंग और पाथ क्रॉसिंग का भी निर्माण करवाया गया। परियोजना में 25.39 हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई सुविधा प्रदान होगी और 70 किसान परिवारों को लाभ मिलेगा। परियोजना के निर्माण पर 51 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। इस दौरान कृषक विकास समूह के प्रधान कर्म सिंह, स्थानीय पंचायत प्रधान दीक्षित नारंग, प्रबंधक समिति के सदस्य तथा अन्य लाभार्थी उपस्थित रहे। जिला परियोजना प्रबंधक मंडी डॉ. हेमराज वर्मा ने कूहल के रख-रखाव के बारे में जानकारी दी।

प्रवाह सिंचाई योजना दत्यार कूहल किसानों को समर्पित

सोलन। हिमाचल प्रदेश फसल विविधीकरण प्रोत्साहन परियोजना चरण-2 में खंड परियोजना प्रबंधन इकाई सोलन के तहत दिनांक 26.01.2025 को प्रवाह सिंचाई योजना दत्यार कूहल का निर्माण पूरा किया गया और कूहल के रख-रखाव की जिम्मेदारी चंडी माता कृषक विकास संघ दत्यार को सौंपी गई। इस परियोजना के तहत प्रदेश में 296 गांवों में सिंचाई सुविधा का विस्तार किया जा रहा है।

अब तक 154 गांवों में यह सुविधा पूरी हो चुकी है और शेष गांवों में कार्य तीव्र गति से चल रहा है। प्रवाह सिंचाई योजना दत्यार से 8.24 हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई प्रदान की गई।

इस योजना के अंतर्गत 40 किसान परिवार लाभान्वित होंगे। इस उप परियोजना के अंतर्गत 1630 मीटर कूहल, एक टैंक की मरम्मत, 300 मीटर एचडीपीई पाईप, 185 मीटर जीआई पाईप, दो डंगों का निर्माण किया गया है। जिसके ऊपर 25 लाख रुपए खर्च किए गए हैं और साथ ही 1,08,140 रुपए के कृषि उपकरण प्रदान किए गए हैं। इस कार्य की शुरुआत 06-09-2024 को की गई थी जिसकी पूर्ण करने की अवधि एक साल की होती है परंतु केवीए और ठेकेदार के सहयोग से यह कार्य सिर्फ चार महीने में पूर्ण हो गया है। इस संबंध में वार्ड मेंबर रुबिन कुमार और अंजु देवी, केवीए प्रधान हरि कृष्ण और लाभार्थी किसानों ने हिमाचल प्रदेश सरकार व जायका परियोजना का धन्यवाद व्यक्त किया और उन्होंने बताया कि पहले कूहल खराब होने के कारण उनके खेतों तक पानी नहीं पहुंच पाता था और समय पर बारिश न होने के कारण वह समय पर फसल की बिजाई नहीं कर पाते थे परंतु कूहल बनने के बाद से वह समय पर फसल की बिजाई कर रहे हैं। ब्लॉक परियोजना प्रबंधक डॉ. अरुण कुमार शर्मा ने कृषि संबंधित उन्नत तकनीकी के बारे में तथा केवीए संघ को सुदृढ़ करने और कूहल के रख-रखाव के बारे में जानकारी प्रदान की। इसके साथ ही दिपांशी ठाकुर (कृषि अधिकारी), शिवानी (कनिष्ठ अभियंता) और केवीए के सदस्य उपस्थित रहे।

दोहग में शेप कैंप का आयोजन

मंडी। दिनांक 18.01.2025 को उपमंडल जोगिंद्रनगर के दोहग गांव में जायका प्रोजेक्ट के तहत से शेप कैंप का आयोजन किया गया।

शिविर में रिसोर्स पर्सन डॉ. एस.के. ठाकुर सेवानिवृत्त निदेशक, बीज प्रमाणीकरण, कृषि विभाग के द्वारा सभी परियोजना में होने वाले कार्य जैसे कि शेप के उद्देश्य, बाजार रणनीतियां उच्च मूल्य और मांग वाली फसलों की खेती, सब्जियों की फसलों में क्षेत्र का विस्तार, सब्जी फसलों की खेती की पद्धतियां के बारे में बताया। प्रोजेक्ट की तरफ से डॉ. अश्वनी कुमार ब्लॉक परियोजना प्रबंधक सरकाघाट ने लिंकेज चैनल बनाकर किसानों को फसलों की उच्च दर प्राप्त करने के लिए जागरूक किया।

इनके अलावा ऋचा बहमन कृषि विशेषज्ञ व गौरव ठाकुर जूनियर इंजीनियर भी कैम्प में मौजूद थे। इस कैंप में 40 लाभार्थियों ने भाग लिया।

गेहूं में खरपतवार नियंत्रण के लिए किसानों को बांटीं दवाइयां

चम्बा। जायका परियोजना के तहत ग्राम पंचायत कोलका में जायका खंड परियोजना के तहत किसानों को गेहूं में खरपतवार को खत्म करने के लिए किसानों को दवाइयां बांटी गईं। इस मौके पर किसानों को गेहूं बिजाई के 45 दिनों के बाद दवा का छिड़काव करने का निर्देश दिया गया। क्षेत्र में कुछ किसानों ने हाल ही में गेहूं की बिजाई की है तो कुछ किसानों ने करीब 25 से 30 दिन पूर्व बिजाई का कार्य पूरा किया है। जायका खंड परियोजना चम्बा के प्रबंधक भानू प्रताप ने बताया कि गेहूं की अच्छी पैदावार के लिए खरपतवार नियंत्रण जरूरी है। खरपतवार गेहूं फसल में भारी नुकसान पहुंचाते हैं तथा यह फसल को दिए जाने वाले खाद-पानी तथा प्रकाश को पौधों से छीन लेते हैं। खरपतवार कई तरह के हानिकारक कीटों व रोगों को भी आश्रय देते हैं। यदि समय पर खरपतवार पर नियंत्रण न किया जाए तो फसल उत्पादन में 30 से 60 फीसद तक की कमी आ सकती है। घास जाति के खरपतवार मुंडेची या कनकी तथा जंगली जई आदि का गेहूं के पौधों से मिलते-जुलते होने के कारण इन्हें निराई-गुड़ाई द्वारा करना संभव नहीं है। अतः इनकी रोकथाम के लिए खरपतवार नाशक दवाओं का प्रयोग बहुत जरूरी है।

फलतनाला में लघुबागवानी सशक्तिकरण एवं संवर्धन के विषय पर एक दिवसीय शिविर का आयोजन

कुल्लू। हिमाचल प्रदेश में चल रहे फसल विविधीकरण प्रोत्साहन परियोजना (चरण-2) जायका-ओडीए, के तहत खण्ड परियोजना प्रबंधन इकाई कुल्लू के बजोरा में चल रही जल बहाव सिंचाई उप-परियोजना फलटनाला में लघुबागवानी सशक्तिकरण एवं संवर्धन के विषय पर एक दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया।

इस शिविर में जल बहाव सिंचाई उप-परियोजना फलतनाला के लाभार्थियों ने हिस्सा लिया। शिविर के दौरान खण्ड परियोजना प्रबंधन इकाई कुल्लू से खण्ड परियोजना प्रबंधक डॉक्टर गोपाल चंद भारद्वाज ने किसानों लघु बागवानी सशक्तिकरण एवं संवर्धन के बारे में लाभार्थियों को विस्तृत रूप से जानकारी दी तथा उन्हें बताया कि शेप एक विस्तार और परामर्शी दृष्टिकोण है, जिसका लक्ष्य किसानों की मानसिकता को 'उगाओ और बेचो' से 'उगाओ और बेचो' मे बदलकर उन्हें बाजारो तक पहुंचने और लाभ उठाने में मदद करना है।

इस शिविर में लगभग 50 किसानों ने भाग लिया। इस एक दिवसीय शिविर में खण्ड परियोजना प्रबंधन इकाई कुल्लू से कृषि अधिकारी सौरभ शर्मा व संजय कुमार उपस्थित रहे।

बहाव सिंचाई योजना घुलानु केवीए को सौंपी

56 लाभार्थी किसानों की 7.79 हेक्टेयर भूमि होगी सिंचित

सरकाघाट। हिमाचल प्रदेश फसल विविधीकरण प्रोत्साहन परियोजना जायका (चरण ।।) के अंतर्गत खंड परियोजना प्रधंधन इकाई सरकाघाट के तहत बहाव सिंचाई योजना घुलानु का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। इस उपपरियोजना के निर्माण कार्य में रुपए 17,04,366 की लागत आई है।

इस परियोजना को 15 जनवरी को कृषक विकास संघ घुलानु को हस्तांतरित कर दिया गया है। इस उपपरियोजना के निर्माण से 7.79 हेक्टेयर क्षेत्र के 56 लाभार्थी किसानों की भूमि को सिंचित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त गांव घुलानु में बुनियादी इंजीनियरिंग कौशल कैंप का आयोजन किया गया। इस एक दिवसीय शिविर में डॉ. हेमराज वर्मा, जिला परियोजना प्रबंधक मंडी, डॉ. अश्वनी कुमार, खंड परियोजना प्रबंधक, सरकाघाट व अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। अब इस परियोजना में सोलर फेंसिंग का कार्य चल रहा है जिसे 31 जनवरी तक पूरा कर दिया जाएगा।

हिमाचल प्रदेश फसल विविधीकरण प्रोत्साहन परियोजना-2 (जायका ओडीए) के स्वामित्व में परियोजना निदेशक द्वारा परियोजना भवन, कृषि परिसर, हमीरपुर-177001 से संपादित, प्रकाशित एवं मुद्रित।
फोन: 01972-223059. ई-मेल : iechpjicaagriculture9@gmail.com